गोदावरी सुगर मिल्स लिमिटेड

बनाम

महाराष्ट्र सरकार व अन्य

(2011 का सिविल अपील संख्या 819)

20 जनवरी, 2011

{आर.वी. रविन्द्रन और ए.के. पटनायक, जेजे.**}**

भारत का संविधान, 1950: अनुच्छेद 226 - का दायरा - भूमि का अधिग्रहण - रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि अधिग्रहण के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल मुआवजा अन्यायपूर्ण और अनुचित था और रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि अधिग्रहण के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित कुल मुआवजा अन्यायपूर्ण और अनुचित था और कब्ज़ा सौंपने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का परमादेश मांगा गया है। - रखरखाव - आयोजित: रिट याचिका सार्वजनिक कानून की प्रकृति की है क्योंकि यह राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के सार्वजनिक कानून कार्यों से संबंधित है और इसलिए सुनवाई योग्य है।

महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961: धारा 26 - मुआवजे पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना – आयोजित: धारा 26 20 वर्षों की अवधि में या 20 वर्षों के अंत में वार्षिक किस्तों में 3% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है। कब्जा लेने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज दर केवल 3% प्रति वर्ष हो सकती है। यदि मुआवजा 20 साल के भीतर नहीं दिया जाता है धारा 26 देय ब्याज दर के बारे में मौन है 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए ब्याज के संबंध में उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा और ब्याज से संबंधित सामान्य न्यायसंगत सिद्धांत लागू होंगे; और न्यायालय के विवेक पर किसी भी उचित दर पर ब्याज दिया जा सकता है। तत्काल मामले में, 20 वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज उचित पाया गया।

अपीलकर्ता बड़े पैमाने पर गन्ने की भूमि का मालिक था। महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961: की धारा 21 के तहत 15.6.1961 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें घोषणा की गई थी कि अपीलकर्ता के पास अधिशेष कृषि भूमि है। इसके बाद अतिरिक्त भूमि पर कब्ज़ा कर लिया गया। 13.11.1978 को अपीलकर्ता ने उक्त भूमि के संबंध में 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अपना दावा प्रस्तुत किया। 13.12.2001 को मुआवजे के निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई और 30.3.2005 को 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ

मुआवजा दिया गया। ब्याज दर से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि चूंकि प्रार्थना केवल ब्याज के माध्यम से धन के भुगतान के लिए की गई थी, इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

तत्काल अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठे, वह यह था कि क्या रिट याचिका धन की वसूली के लिए थी और इसलिए सुनवाई योग्य नहीं थी; और क्या प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत देय मुआवजे पर केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित था।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया कि:-

1.1. याचिका इस घोषणा के लिए थी कि नोटिस दिनांक 30.3.2005 ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि 12127.4 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ब्याज सहित कुल मुआवजा 88,77,538/- रुपये अन्यायपूर्ण और मनमाना और भेदभावपूर्ण था क्योंकि इसमें केवल ब्याज की पेशकश की गई थी। मुआवजे की राशि पर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और कब्जा सौंपने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। रिट याचिका सार्वजनिक कानून प्रकृति की थी क्योंकि यह राज्य

सरकार और उसके अधिकारियों के सार्वजनिक कानून कार्यों से संबंधित थी और इसलिए सुनवाई योग्य थी। {पैरा 6} [187-जी-एच; 188-ए-बी, ई]

सुगनमल बनाम एमपी राज्य - एआईआर 1965 एससी 1740; यूपी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम कनोरिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड 2001 (2) एससीसी 549; एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2004 (3) एससीसी 553 - संदर्भित।

1.2. आम तौर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी अनुबंध के उल्लंघन या दावेदारों को देय धनराशि का भुगतान करने के अपकृत्य से उत्पन्न नागरिक दायित्व को लागू करने के लिए याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पीड़ित पक्ष को सिविल मुकदमे में इस सवाल पर विरोध करना होगा। लेकिन राज्य या उसके अधिकारियों के वैधानिक कार्यों को लागू करने के लिए रिट कार्यवाही में धन के भुगतान का आदेश दिया जा सकता है। [पैरा 7(i)] [189-बी-सी]

वर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य (1962) सप्लिमेंट 1 एससीआर 242 - पर भरोसा किया गया।

1.3. यदि किसी अधिकार का उल्लंघन हुआ है - चाहे वह मौलिक अधिकार हो या वैधानिक अधिकार - और पीड़ित पक्ष अधिकार के प्रवर्तन

के लिए अदालत में आता है, यदि अदालत केवल ऐसे अधिकार के अस्तित्व की घोषणा करती है या इस तथ्य की घोषणा करती है कि मौजूदा अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो इससे पूरी राहत नहीं मिलेगी। उच्च न्यायालय, मौलिक या वैधानिक अधिकारों को लागू करते समय, कानून के अधिकार के बिना सरकार द्वारा प्राप्त धन के भुगतान का आदेश देकर परिणामी राहत देने की शक्ति रखता है। [पैरा 7(ii)] [189-सी-डी]

मध्यप्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई एयर 1964 एससी 1006-पर भरोसा किया गया।

1.4. केवल धन वापसी का आदेश देने के उद्देश्य से परमादेश रिट जारी करने की याचिका पर आम तौर पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी वापसी पर याचिकाकर्ता अधिकार का दावा करता है। रिफंड चाहने वाले पीड़ित पक्ष को राशि का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, हालाँकि उच्च न्यायालयों के पास पैसे के भुगतान के लिए अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने की शक्ति है। [पैरा 7(iii)] [189- एच ई-एफ]

सुगनएमएफएल बनाम मध्य प्रदेश राज्य एआईआर 1965 एससी 1740 - पर भरोसा किया गया।

1.5. उन मामलों के बीच अंतर है जहां एक दावेदार केवल धन वापस प्राप्त करने की राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और जहां मूल्यांकन आदि के आदेश को रद्द करने के बाद परिणामी राहत के रूप में धन वापसी की मांग की जाती है। जबकि अवैध रूप से एकत्र किए गए कथित धन को वापस करने के लिए राज्य को केवल परमादेश जारी करने की प्रार्थना करने वाली याचिका आम तौर पर सुनवाई योग्य नहीं है, यदि आरोप यह है कि मूल्यांकन क्षेत्राधिकार के बिना था और एकत्र किए गए कर कानून के अधिकार के बिना थे और, इसलिए, प्रतिवादियों के पास कानून के किसी अधिकार के बिना एकत्र किए गए धन को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं था, उच्च न्यायालय के पास रिट याचिका में धन वापसी का निर्देश देने की शक्ति है। [पैरा 7{iv)] [189-जी-एच; 190-ए-बी]

सलोना टी कंपनी लिमिटेड बनाम कर अधीक्षक, नंगाव (1988) 1 एससीसी 401 - पर भरोसा किया गया।

1.6. यह कहना एक बात है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अवैध रूप से एकत्र किए गए धन की वापसी के लिए परमादेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है। यह कहना एक और बात है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसी शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां

तथ्य विवादित नहीं हैं, जहां धन का संग्रह कानून के अधिकार के बिना किया गया था और अनुचित संवर्धन का कोई मामला नहीं था, वहां नागरिकों को धन वापसी की राहत देने से इंकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में भी जहां उपकर का संग्रहण, लेवी या कर को असंवैधानिक या अमान्य माना जाता है, धनवापसी एक स्वचालित परिणाम नहीं है, लेकिन किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कई आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है। [पैरा 7(v)] [190-सी-ई)

उ.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम कनोरिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड 2001 (2) धारा 549 - पर आधारित।

1.7. जहां लिस का सार्वजनिक कानून चरित्र है, या इसमें राज्य या उसके अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक कानून कार्यों से उत्पन्न होने वाला प्रश्न शामिल है, जहां लिस की प्रकृति सार्वजनिक कानून की है, या इसमें राज्य या उसके अधिकारियों की ओर से सार्वजनिक कानून कार्यों से उत्पन्न होने वाला प्रश्न शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कानून उपाय के माध्यम से न्याय तक पहुंच से इंकार नहीं किया जाएगा। [पैरा 7(vi)] [190-एफ]

संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2005) 8 एससीसी 242 - पर आधारित।

2.1. अधिनियम की धारा 24 के तहत कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम की धारा 21(4) के तहत अधिशेष भूमि का कब्जा लेने के बाद, इच्छुक व्यक्तियों को अपने दावे दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाए। अधिनियम की धारा 25 मुआवजे के निर्धारण और उसके बंटवारे का प्रावधान करती है। धारा 26 मुआवजे की राशि के भुगतान के तरीके से संबंधित है। उक्त धारा 20 वर्षों की अवधि में या 20 वर्षों के अंत में वार्षिक किस्तों में 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है। इसमें हस्तांतरणीय बांड या नकद द्वारा भुगतान करने पर भी विचार किया गया है। धारा 26 की उपधारा (3) नकद द्वारा मुआवजे के भुगतान को सक्षम बनाती है, ऐसे मामलों में जहां इसका भुगतान ऐसे बांड द्वारा नहीं किया जा सकता है, ब्याज दर में गड़बड़ी नहीं करता, जो 20 वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष है, इसकी उपधारा (1) में प्रावधान किया गया है। चाहे भुगतान हस्तांतरणीय बांड द्वारा किया गया हो या नकद द्वारा, कब्जा लेने की तारीख से 20 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज दर केवल 3% प्रति वर्ष हो सकती है। [पैरा 11] [192- जी-एच; 193-एफ-एच]

2.2. यदि मुआवजे का भुगतान 20 वर्षों के भीतर नहीं किया जाता है तो धारा 26 देय ब्याज दर के बारे में मौन है। धारा 26 कब्ज़ा लेने की तारीख से 20 साल के भीतर 3% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है; और 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, ब्याज के संबंध में उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा एवं ब्याज से संबंधित सामान्य न्यायसंगत सिद्धांत लागू होंगे; और न्यायालय के विवेक पर किसी भी उचित दर पर ब्याज दिया जा सकता है। 20 वर्षों के बाद 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज न्यायसंगत सिद्धांतों पर उचित और देय होगा। [पैरा 12] [194-ए-सी]

भारत संघ बनाम परमाल सिंह (2009) 1 एससीसी 618 - पर आधारित।

2.3. प्रतिवादियों को मुआवजा राशि पर कब्जा लेने की तारीख से भुगतान की तारीख तक, पहले बीस वर्षों के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद (अर्थात् 20 की अवधि की समाप्ति की तारीख) से 31.3.2005 (भुगतान की तारीख) तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इस प्रकार गणना किए गए ब्याज में से, 31.3.2005 को ब्याज के लिए पहले से भुगतान की गई 45,54,881/84 रुपये की राशि काट ली जाएगी और शेष राशि आज से

तीन महीने के भीतर प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ताओं को भुगतान की जाएगी। [पैरा 13) [194-डी-एच; 195-ए-बी]

केस कानून संदर्भ:

एआईआर 1965 एससी 1740	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
2001 (2) एससीसी 549	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
2004 (3) एससीसी 553	संदर्भित किया गया है	पैरा 7
(1962) अनुपूरक 1 एससीआर 242	उस पर भरोसा करें	पैरा 7(i)
एआईआर 1964 एससी 1006	उस पर भरोसा करें	पैरा7(ii)
एआईआर 1965 एससी 1740	उस पर भरोसा करें	पैरा 7(iii)
(1988) 1 एससीसी 401	उस पर भरोसा करें	पैरा 7(iv)
2001 (2) एससीसी 549	उस पर भरोसा करें	पैरा 7(v)
(2005) 8 एससीसी 242	उस पर भरोसा करें	पैरा 7(vi)
(2009) 1 एससीसी 618	उस पर भरोसा करें	पैरा 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 819/2011।

उच्च न्यायालय बॉम्बे 2005 की रिट याचिका संख्या 6375 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 04.10.2005 से।

पी.एच. पारेख, सुमित गोयल, आनंद झा, शिवानी बी (पारेख एंड कंपनी के लिए) अपीलकर्ता के लिए।

माधवी दीवान, संजय वी. खरदे, आशा गोपालन नायर प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय आर.वी.रवेन्द्रन, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत की गई।

2. अपीलकर्ता काफी हद तक गन्ने की भूमि का मालिक था। विशेष उप कलेक्टर, अहमदनगर ने महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 21 के तहत दिनांक 15.6.1961 को एक अधिसूचना जारी की जिसमें घोषणा की गई कि अपीलकर्ता के पास 12127.4 एकड़ अधिशेष कृषि भूमि है। इसके अनुसरण में, साकरवाड़ी में 7407 एकड़ और 33½ गुंटास भूमि और लक्ष्मीवाड़ी में 2910 एकड़ और 4 गुंटा भूमि का कब्ज़ा 25.5.1968 को ले लिया गया। साकरवाड़ी में अन्य 608 एकड़ और 38½ गुंटास और लक्ष्मीवाड़ी में 525 एकड़ 1% गुंटा का कब्ज़ा 23.1.1976 को लिया गया। अंततः लक्ष्मीवाड़ी में शेष 99 एकड़ 13 गुंटा का कब्ज़ा 6.4.1990 को ले लिया गया।

3. 13.11.1978 को अपीलकर्ता ने अधिनियम की धारा 24(1) के तहत संपूर्ण भूमि (99 एकड़ 13 गुंटास को छोड़कर जो बाद में ली गई थी)

के संबंध में अपना दावा प्रस्तुत किया। अपीलकर्ता द्वारा कई अनुस्मारक भेजे गए जिसमें देरी पर प्रकाश डाला गया और 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के भुगतान की मांग की गई। अंततः 13.12.2001 को अधिनियम की धारा 24(1) और (2) के तहत जांच के लिए नोटिस जारी करके मुआवजे के निर्धारण की कार्यवाही शुरू की गई। दूसरे प्रतिवादी ने दिनांक 30.3.2005 को एक फैसला दिया, जिसमें देय राशि 88,77,538.49 रुपये निर्धारित की गई, जिसमें मुआवजे के रूप में 43,22,656.65 रुपये और कब्जे की तारीख से 31.3.2004 तक प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से ब्याज के रूप में 45,54,881.84 रुपये शामिल थे। अपीलकर्ता के विरोध के तहत दिनांक 31.3.2005 को उक्त भुगतान स्वीकार कर लिया गया।

4. केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से दिए गए ब्याज से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या 6375/2005) दायर की। अपीलकर्ता ने इस फैसले को रद्द करने की मांग की, क्योंकि इसमें 3% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था और कब्जे की डिलीवरी की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% की दर से ब्याज देने की प्रार्थना की थी। अपीलकर्ता के अनुसार, रिट याचिका (डब्ल्यूपी संख्या, 6375/2005) की तिथि पर 97,66,189.16 रुपये की राशि बकाया थी, जो मूल राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना करने पर 3% के

अंतर के बराबर थी। उच्च न्यायालय ने उक्त याचिका को प्रवेश स्तर पर दिनांक 4.10.2005 के आक्षेपित आदेश द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थना केवल धन के भुगतान (ब्याज के माध्यम से) के लिए थी, रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी और अपीलकर्ता किसी भी अन्य उपाय जो उपलब्ध हो अपनाने के लिए स्वतंत्र था। उक्त आदेश को इस अपील में विशेष अनुमति द्वारा चुनौती दी गयी है।

5. इस अपील में आपके विचारार्थ निम्नलिखित दो प्रश्न उठते हैं :

(i) क्या रिट याचिका "पैसे की वसूली" के लिए थी और इसलिए सुनवाई योग्य नहीं है?

(ii) क्या दूसरे प्रतिवादी को महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोतों की सीमा) अधिनियम, 1961 की धारा 25 के तहत देय मुआवजे पर केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना उचित था?

<u>पुनः प्रश्न संख्या (i)</u>

6. रिट याचिका इस घोषणा के लिए थी कि नोटिस दिनांक 30.3.2005 ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि 12127.4 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के लिए ब्याज सहित कुल मुआवजा 88,77,538/- रुपये अन्यायपूर्ण और मनमाना और भेदभावपूर्ण था क्योंकि इसमें केवल ब्याज

की पेशकश की गई थी, मुआवज़ा राशि पर 3% प्रति वर्ष की दर और कब्ज़ा सौंपने की तारीख से वास्तविक भुगतान की तारीख तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवज़ा का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। अपीलकर्ता ने रिट याचिका में तर्क दिया कि कृष्णकुमार विट्ठलराव जामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य (1986 का डब्ल्यूपी संख्या 83, 29.6.1991 को निर्णय किया गया) और श्री चांगदेव शुगर मिल्स बनाम महाराष्ट्र राज्य (डब्ल्यूपी) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों को ध्यान में रखते हुए क्रमांक 3805/2000 दिनांक 7.7.2000 को निर्णय किया गया) जिसमें उक्त अधिनियम के तहत देय मुआवजे के संबंध में 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था, दूसरे प्रतिवादी ने 3% प्रति वर्ष की कम दर पर ब्याज देने में अवैध रूप से काम किया। इसलिए, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका साधारण धन दावे से संबंधित नहीं थी। इसमें ब्याज दर के मुद्दे की जांच या निर्धारण करने से पहले, राज्य सरकार और उसके अधिकारियों की ओर से उनके वैधानिक कार्यों के अभ्यास में मनमानी और भेदभाव के आरोपों के संबंध में निर्णय की आवश्यकता थी। मुख्य रूप से, रिट याचिका सार्वजनिक कानून प्रकृति की थी क्योंकि यह राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के सार्वजनिक कानून कार्यों से संबंधित थी, और इसलिए सुनवाई योग्य थी।

7. उच्च न्यायालय ने सुगनमल बनाम एमपी-एआईआर 1965 एससी 1740 राज्य में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते यह माना गया है कि रिट याचिका में प्रार्थना ब्याज के भुगतान के लिए एक है, इसे धन के दावे को लागू करने के लिए दायर की गई रिट याचिका माना जाना चाहिए और इसलिए, यह सुनवाई योग्य नहीं है। सुगनमल के फैसले को बाद के कई मामलों में समझाया और प्रतिष्ठित किया गया है, जिसमें यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम कनोरिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड - 2001 (2) एससीसी 549 और एबीएल इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड - 2004 (3) शामिल हैं एससीसी 553. कानूनी स्थिति तब स्पष्ट हो जाती है जब सुगनमल के फैसले को इस मुद्दे पर इस अदालत के अन्य फैसलों के साथ पढ़ा जाता है, जिसका संदर्भ नीचे दिया गया है:

(I) आम तौर पर किसी अनुबंध के उल्लंघन या दावेदारों को देय धनराशि का भुगतान करने के अपकृत्य से उत्पन्न सिविल दायित्व को लागू करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। पीड़ित पक्ष को सिविल मुकदमे में इस सवाल पर विरोध करना होगा। लेकिन राज्य या उसके अधिकारियों के वैधानिक कार्यों को लागू करने के लिए रिट कार्यवाही में धन के भुगतान

का आदेश दिया जा सकता है। [बर्मा कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाम उड़ीसा राज्य - (1962) अनुपूरक 1 एससीआर 242].

(ii) यदि किसी अधिकार का उल्लंघन किया गया है - चाहे वह मौलिक अधिकार हो या वैधानिक अधिकार - और पीड़ित पक्ष अधिकार के प्रवर्तन के लिए अदालत में आता है, यदि अदालत केवल ऐसे अधिकार के अस्तित्व की घोषणा करती है या इस तथ्य की घोषणा करती है कि मौजूदा अधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो इससे पूरी राहत नहीं मिलेगी। उच्च न्यायालय, मौलिक या वैधानिक अधिकारों को लागू करते समय, कानून के अधिकार के बिना सरकार द्वारा किए गए धन के भुगतान का आदेश देकर परिणामी राहत देने की शक्ति रखता है (मध्य प्रदेश राज्य बनाम भाईलाल भाई -एआईआर 1964 एससी 1006 के तहत).

(iii) आम तौर पर परमादेश रिट जारी करने की याचिका पर केवल धन की वापसी का आदेश देने के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा, जिसकी वापसी पर याचिकाकर्ता अधिकार का दावा करता है। रिफंड चाहने वाले पीड़ित पक्ष को राशि का दावा करने के लिए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, हालांकि उच्च न्यायालयों को पैसे के भुगतान के लिए अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित आदेश पारित करने की शक्ति है। (सुगनमल बनाम मध्य प्रदेश राज्य - एआईआर 1965 एससी 1740).

(iv) उन मामलों के बीच अंतर है जहां एक दावेदार केवल रिफंड प्राप्त करने की राहत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और जहां मूल्यांकन के आदेश को रद्द करने के बाद परिणामी राहत के रूप में रिफंड की मांग की जाती है, जबकि अवैध रूप से एकत्र किए गए कथित धन को वापस करने के लिए राज्य को केवल परमादेश जारी करने की प्रार्थना करने वाली याचिका आम तौर पर सुनवाई योग्य नहीं है, यदि आरोप यह है कि मूल्यांकन अधिकार क्षेत्र के बिना था और एकत्र कर कानून के अधिकार के बिना था और इसलिए प्रतिवादियों के पास कानून के अधिकार के बिना एकत्र किए गए धन को रखने का कोई अधिकार नहीं था, उच्च न्यायालय के पास एक रिट याचिका में धन वापसी का निर्देश देने की शक्ति है [सैलोना टी कंपनी लिमिटेड बनाम कर अधीक्षक, नंगाव (1988) 1 एससीसी 401 के माध्यम से].

(v) यह कहना एक बात है कि उच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अवैध रूप से एकत्र किए गए धन की वापसी के लिए परमादेश जारी करने की कोई शक्ति नहीं है और यह कहना एक बात है कि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ऐसी शक्ति का प्रयोग संयमित ढंग से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहां तथ्य विवादित नहीं हैं, जहां धन का संग्रह कानून के अधिकार के बिना था और अनुचित संवर्धन का कोई मामला नहीं था, वहां नागरिकों को रिफंड

की राहत से इनकार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। लेकिन ऐसे मामलों में भी जहां उपकर, लेवी या कर का संग्रह असंवैधानिक या अमान्य माना जाता है, रिफंड एक स्वचालित परिणाम नहीं है, बल्कि किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर कई आधारों पर अस्वीकार किया जा सकता है। (यू.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम कनोरिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड - 2001 (2) एससीसी 549 देखें)।

(vi) जहां लिस की प्रकृति सार्वजनिक कानून है, या इसमें राज्य या उसके अधिकारियों के सार्वजनिक कानून कार्यों से उत्पन्न होने वाला प्रश्न शामिल है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सार्वजनिक कानून उपाय के माध्यम से न्याय तक पहुंच से इंकार नहीं किया जाएगा। [देखें संजना एम. विग बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2005) 8 एससीसी 242.]

इसलिए हमारा विचार है कि सुगनमल पर निर्भरता गलत थी, यह मानना कि अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी।

पुनः प्रश्न **(ii)**

8. अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि मुआवजा राशि तब देय हो गई जब भूमि पर कब्जा ले लिया गया था और इसे अनुचित तरीके से रोका गया था, अपीलकर्ता मुआवजे की राशि पर 9% प्रति वर्ष की उचित दर पर भुगतान की तिथि तक ब्याज का हकदार था। अपने दावे के समर्थन में

उन्होंने कृष्णा कुमार और श्री चांगदेव चीनी मिलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो फैसलों पर भरोसा किया, जहां इसी तरह के मामलों में 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया गया था। दूसरी ओर प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 26 में यह बताने के लिए पर्याप्त संकेत थे कि ब्याज की दर केवल 3% होनी चाहिए, और इसलिए ब्याज केवल 3% प्रति वर्ष ही दिया जा सकता है। प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि बॉम्बे उच्च न्यायालय के दो निर्णय अलग-अलग थे क्योंकि वे उन मामलों से संबंधित थे जहां 31.03.2005 को 3% प्रति वर्ष ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और इसलिए उक्त निर्णय लागू नहीं होंगे। यह बताया गया कि कृष्णकुमार में अधिशेष भूमि का कब्ज़ा वर्ष 1973 में लिया गया था, लेकिन रिट याचिका के निपटारे की तारीख तक, कोई मुआवजा नहीं दिया गया था; श्री चांगदेव चीनी मिल में अधिशेष भूमि का कब्ज़ा राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया था और देय मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था और यद्यपि देय मुआवजा 29.12.1966, 23.2.1967 और 13.12.1968 को निर्धारित किया गया था, इसका भुगतान नहीं किया गया था; और उन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने वास्तविक भुगतान की तारीख की दर से ब्याज के साथ मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया था। वैकल्पिक रूप से यह प्रस्तुत किया

गया कि उक्त निर्णयों में अधिनियम की धारा 26 पर विचार न करते हुए, वे सही निर्णय नहीं लिए गए।

9. प्रतिवादियों की विद्वान वकील श्रीमती माधवी दीवान की दलीलों में काफी दम है कि कृष्ण कुमार और चांगदेव मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले सही नहीं हैं, क्योंकि मुआवजे के विलंबित भुगतान पर 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देते समय वे अधिनियम की धारा 26 को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं।

10. मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज कब और किन परिस्थितियों में दिया जा सकता है, इस सवाल पर इस न्यायालय ने भारत संघ बनाम परमाल सिंह - (2009) 1 एससीसी 618 में विचार किया था। इस न्यायालय ने पहले सामान्य सिद्धांत और फिर उसके अपवादों का उल्लेख किया, जैसा कि नीचे दिया गया है:

> "जब कोई संपत्ति अर्जित की जाती है और कानून निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित मुआवजे के भुगतान का प्रावधान करता है, तो आमतौर पर अधिग्रहण के अनुसरण में कब्जा लेने के समय मुआवजे का भुगतान करना होगा। न्यायसंगत सिद्धांतों को लागू करके, अदालतें हमेशा किसी संपत्ति के अधिग्रहण के संबंध में मुआवजे के विलंबित भुगतान पर

ब्याज दिया गया... उक्त सामान्य सिद्धांत दो परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। एक वह है जहां कोई प्रतिमा रुचि को निर्दिष्ट या नियंत्रित करती है। उस स्थिति में, ब्याज केवल मूर्ति के प्रावधान के संदर्भ में देय होगा। दूसरा वह है जहां अधिग्रहण से संबंधित एक प्रतिमा या अनुबंध विशेष रूप से मुआवजे की राशि पर ब्याज के भुगतान को रोकता है या प्रतिबंधित करता है। उस स्थिति में ब्याज नहीं दिया जाएगा. जहां ब्याज के बारे में कानून मौन है, और ब्याज के भुगतान के बारे में कोई स्पष्ट रोक नहीं है, मुआवजे के भुगतान में किसी भी देरी या अधिग्रहण के लिए बढ़े हुए मुआवजे के लिए न्यायसंगत आधार पर उचित दरों पर ब्याज देने की आवश्यकता होगी"

यह न्यायालय, भारत रक्षा अधिनियम, 1962 (जिसमें ब्याज के भुगतान की आवश्यकता या निषेध करने वाला कोई प्रावधान नहीं था) के तहत एक अधिग्रहण से निपटते हुए, 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने के फैसले को बरकरार रखा।

11. अधिनियम की धारा 24 के तहत कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि अधिनियम की धारा 21 (4) के तहत अधिशेष भूमि का कब्जा लेने के बाद, इच्छुक व्यक्तियों को अपने दावे दर्ज कराने के लिए सार्वजनिक नोटिस

जारी किया जाए। अधिनियम की धारा 25 मुआवजे के निर्धारण और उसके बंटवारे का प्रावधान करती है। धारा 26 मुआवजे की राशि के भुगतान के तरीके से संबंधित है और इसे नीचे दिया गया है:

> "26. (1) मुआवजे की राशि, उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन, प्रति वर्ष तीन प्रतिशत ब्याज वाले हस्तांतरणीय बांड में देय हो सकती है।
>
> (2) बांड होंगे –
>
> ए) निम्नलिखित मूल्यवर्ग में से, अर्थात्:- 50 रुपये; 100 रुपये; 200 रुपये; 500 रुपये; 1,000 रुपये; 5,000 रुपये; और 10,000 रुपये; और
>
> (बी) दो वर्गों में - एक जारी होने की तारीख से बीस साल की अवधि के दौरान मूलधन और ब्याज की समान वार्षिक किस्त द्वारा चुकाया जाना है, और दूसरा जारी होने की तारीख से बीस साल के अंत में सममूल्य पर प्रतिदेय होगा। मुआवज़ा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास यह विकल्प होगा कि वह बांड के एक या दूसरे वर्ग में, या आंशिक रूप से एक वर्ग में और आंशिक रूप से दूसरे वर्ग में भुगतान का चयन करे।

(3) जहां मुआवजे की राशि या उसके किसी हिस्से का भुगतान उपरोक्त मूल्यवर्ग में नहीं किया जा सकता है, वहां इसका भुगतान नकद में किया जा सकता है।

(बल दिया गया)

उक्त धारा 20 वर्षों की अवधि में या 20 वर्षों के अंत में वार्षिक किस्तों में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है। इसमें हस्तांतरणीय बांड या नकद द्वारा भुगतान करने पर भी विचार किया गया है। धारा 26 की उप-धारा (3) नकदी द्वारा मुआवजे के भुगतान को सक्षम करती है, ऐसे मामलों में जहां इसका भुगतान ऐसे बांडों द्वारा नहीं किया जा सकता है, ब्याज की दर को प्रभावित नहीं करता है, जो कि 20 वर्षों के लिए 3 प्रतिशत प्रति वर्ष है, जो कि इसकी उप-धारा (1) में प्रदान किया गया है। इसलिए हमारा विचार है कि चाहे भुगतान हस्तांतरणीय बांड द्वारा किया जाए या नकद द्वारा, कब्जा लेने की तारीख से 20 साल की अवधि के लिए ब्याज दर केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष हो सकती है।

12. अगला प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह ब्याज दर के बारे में है यदि भुगतान 20 वर्षों के बाद भी नहीं किया जाता है, और क्या यह 20 वर्षों के बाद भी केवल 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से

होना चाहिए। धारा 26 देय ब्याज दर के बारे में चुप है, यदि मुआवजा 20 साल के भीतर नहीं दिया जाता है। इसलिए हमारा विचार है कि धारा 26 कब्ज़ा लेने की तारीख से 20 साल के भीतर 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के भुगतान पर विचार करती है; और 20 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, ब्याज के संबंध में उक्त प्रावधान लागू नहीं होगा और ब्याज से संबंधित सामान्य न्यायसंगत सिद्धांत लागू होंगे; और न्यायालय के विवेकानुसार ब्याज किसी भी उचित दर पर दिया जा सकता है। 20 वर्षों के बाद 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज न्यायसंगत सिद्धांतों पर उचित और देय होगा।

13. इसलिए हम इस अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और प्रतिवादियों को मुआवजे की राशि पर कब्जे की तारीख से भुगतान की तारीख तक, पहले बीस वर्षों के लिए 3% प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद (अर्थात 20 साल की अवधि की समाप्ति की तारीख से) 31.3.2005 (भुगतान की तारीख) तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश देते हैं।

कब्ज़ा लेने की तिथि	मूल धन	अवधि	ब्याज की दर
20.5.1968	राशि 41,31,821.59	20.5.1968 से 19.5.1988	3 प्रतिशत प्रति वर्ष

		20.51988 से 31.3.2005	6 प्रतिशत प्रति वर्ष
23.1.1996	राशि 1,77,478.61	23.1.1976 से 22.1.1996 23.1.1996 से 31.3.2005	3 प्रतिशत प्रति वर्ष 6 प्रतिशत प्रति वर्ष
6.4.1990	राशि 13,365.45	6.4.1990 से 31.3.2005	3 प्रतिशत प्रति वर्ष

इस प्रकार गणना किए गए ब्याज में से, 31.3.2005 को ब्याज के लिए पहले से भुगतान की गई 45,54,881/84 की राशि काट ली जाएगी और शेष राशि आज से तीन महीने के भीतर प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ताओं को भुगतान की जाएगी।

डी.जी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनु यादव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।